

## वर्ष/देश देशांतर : कर्जमाफी और अर्थव्यवस्था

### संदर्भ

मौसम की मार, कर्ज की मार, फसलों का उचित रख-रखाव और उपज का सही कीमत न मिलना इस धरती पुत्र की कमर तोड़ देती है और नतीजा किसानों की आत्महत्या के रूप में सामने आता है। चुनावी सीजन में राजनीतिक पार्टियाँ किसानों की सुध लेती हैं और उन्हें साधने के लिये कर्जमाफी का शगुना छेड़ देती हैं, बिना यह सोचे-समझे कि इसका नकारात्मक और दूरगामी प्रभाव क्या होगा?

- क्या कर्जमाफी से किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकलेगा? अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा? और सबसे अहम यह कि क्या आज तक हुई कर्जमाफी से अननदाता की कसिमत बदली है?
- इन सवालों पर इस वक्त देश में बहस तेज़ है। नीतिआयोग ने इसे अर्थव्यवस्था सहित किसानों के लिये भी सही नहीं बताया है।
- नीतिआयोग ने स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @ 75 में किसानों की आमदनी को दोगुना करने के साथ ही आधारभूत संरचना के विकास की बात कही है।

### पृष्ठभूमि

- दरअसल, 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने पहली बार पूरे देश में किसानों का करीब 10 हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। उसके बाद NDA सरकार ने 2008-09 के बजट में करीब 71 हजार करोड़ रुपए का कर्जमाफी का एलान किया।
- वहीं राज्यों की बात करें तो 2014 से अब तक सात राज्यों ने करीब 1 लाख 82 हजार 802 करोड़ तक के कर्जमाफी का एलान किया।
- 2014 में आंध्र प्रदेश ने 24 हजार करोड़, तेलंगाना ने 17 हजार करोड़ जबकि 2016 में तमिलनाडु ने 6 हजार करोड़ और वर्ष 2017 में महाराष्ट्र ने 34 हजार करोड़, वहीं उत्तर प्रदेश ने 36 हजार करोड़ और पंजाब ने 1 हजार करोड़ रुपए कर्जमाफी का एलान किया।
- अगर इसमें हाल के तीन राज्यों यानी मध्य प्रदेश के संभावित 35 हजार से 38 हजार करोड़, छत्तीसगढ़ के लगभग 6 हजार करोड़ और राजस्थान के 18 हजार करोड़ रुपए के कर्जमाफी को जोड़ दिया जाए तो यह आँकड़ा काफी बढ़ जाएगा।

### क्या कर्जमाफी किसानों की समस्याओं का समाधान है?

- क्या कर्जमाफी किसानों की समस्या का समाधान है? इस पर देश में बहस तेज़ हो गई है। जानकारों का मानना है कि यह राज्यों के वित्तीय हालत के लिये सही नहीं है।
- नीतिआयोग का भी मानना है कि कर्जमाफी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं है। इससे पहले RBI भी कई बार कह चुका है कि कर्जमाफी अर्थव्यवस्था की सेहत के लहजा से सही नहीं है।
- किसान देश के अननदाता हैं। लेकिन उनके सामने समस्याएँ भी कई हैं, उनमें से एक है कर्ज की समस्या। कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से कई किसान आत्महत्या तक कर रहे हैं।
- सवाल यह उठता है कि यह अर्थव्यवस्था के लहजा से कर्जमाफी कतिना कारगर उपाय है। नीतिआयोग का मानना है कि कर्जमाफी जैसे कदमों से सरिफ कुछ किसानों को मदद पहुँचेगी। यह किसानों की समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान नहीं है।
- किसानों की समस्याओं को दूर करने से जुड़ी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को वर्तमान सरकार ने स्वीकार किया है।
- किसानों का ऋण साढ़े 10 लाख करोड़ तक बढ़ गया है राज्य सरकारों को कर्जमाफी का फैसला अपनी वित्तीय स्थितिको देखकर उठाना चाहिये।
- इससे किसानों के सरिफ एक तबके को लाभ होगा। गरीब राज्यों के सरिफ 10 से 15 प्रतिशत किसान कर्जमाफी से लाभान्वित हो सकते हैं। क्योंकि ऐसे राज्यों में बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या बहुत कम है। यहाँ तक कि 25 प्रतिशत किसान भी संस्थागत कर्ज नहीं लेते।
- कृषि कर्ज से संबंधित एक पहलू यह भी है कि किसान जो कर्ज खेती के लिये लेते हैं उसे पूरा इस्तेमाल खेती को बढ़ावा देने के लिये नहीं हो पाता।
- कुछ राज्यों में किसान कृषि कर्ज के तीन-चौथाई का इस्तेमाल खेती के लिये नहीं बल्कि दूसरे नीजी ज़रूरतों के लिये कर लेते हैं।
- नीतिआयोग का यह भी मानना है कि राज्यों में किसानों के कर्ज लेने के मामले में संस्थागत पहुँच को लेकर भारी अंतर है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार कृषि कर्जमाफी से मदद नहीं मिलती।
- इसमें दो राय नहीं है कि कर्जमाफी से राज्यों की अर्थव्यवस्था के सेहत पर नकारात्मक असर पड़ता है। कृषि से जुड़े ज़्यादातर मामले राज्य सरकारों के दायरे में आता है। लेकिन वडिंबना है कि ज़्यादातर राजनीतिक दल स्थायी समाधान पर ज़ोर देने की बजाय राजनीतिक लाभ के लिये कर्जमाफी का फारमूला अपनाते हैं।
- मध्य प्रदेश के उदाहरण से समझें तो राज्य सरकार के कर्जमाफी के फैसले से देश की जनता पर 34 से 38 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आ जाएगा।

- राजस्थान में कर्ज़माफी से सरकारी खजाने पर करीब 18 हज़ार करोड़ का बोझ आया।
- इससे पहले देश का केंद्रीय बैंक रज़र्व बैंक आफ इंडिया भी कई बार कह चुका है कि कर्ज़माफी जैसे कदमों से देश को राजस्व का बहुत नुकसान होता है और ऐसे फैसले देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालते हैं।

### कर्ज़ माफी का अर्थशास्त्र तथा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- सवाल यह है कि कर्ज़माफी के फैसले का सकारात्मक प्रभाव राज्यों और किसानों पर कतिना पड़ेगा। यह सवाल इसलिये महत्वपूर्ण है कि आखिर इस कर्ज़माफी से किसान को फायदा होगा या नुकसान।
- जानकारों की मानें तो यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला है। इसका असर किसानों और राज्य की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक रूप से पड़ेगा।
- दरअसल, इस कर्ज़माफी का फायदा कुछ हद तक बड़े किसानों को मिल सकता है लेकिन छोटे किसानों पर इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि बड़े किसान कुछ हद तक कर्ज़ चुकाने की स्थिति में होते हैं, और वही कर्ज़ भी ले पाते हैं। इसलिये इसका फायदा भी वही उठा सकते हैं।
- जबकि छोटे किसानों को इसका कोई खास फायदा नहीं होगा, वहीं दूसरी तरफ राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसका काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- पछिल्ले कुछ वर्षों के आँकड़ों को अगर देखें तो राज्यों के मुकाबले केंद्र पर राजकोषीय घाटा ज़्यादा है। लेकिन जिस प्रकार राज्य सरकारों ने कर्ज़माफी की घोषणा की है उससे राजकोषीय घाटा और ज़्यादा बढ़ जाने की उम्मीद है।
- इसकी भरपाई के लिये राज्यों को केंद्र से या फिर दूसरे विकल्पों के ज़रिये कर्ज़ लेना होगा और दूसरे विकास कार्य कहीं-न-कहीं इसकी वजह से प्रभावित होंगे।
- इसके अलावा, बाहर से कर्ज़ लेने पर राज्य सरकारों को इसकी अदायगी के लिये ज़्यादा ब्याज देना होगा।
- दरअसल, कर्ज़माफी को पूरी तरह राज्य ही वहन करता है। कर्ज़माफी का सबसे बड़ा असर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई रेटिंग पर पड़ता है।
- इस तरह की एजेंसी कभी भी भारत को बेहतर रेटिंग नहीं देती है। क्योंकि रेटिंग देते समय सिर्फ केंद्र सरकार को ही नहीं देखा जाता बल्कि इसमें राज्यों का भी काफी योगदान होता है।
- लगातार राजकोषीय घाटा बढ़ने से इस तरह की एजेंसियाँ हमेशा से ही भारतीय अर्थव्यवस्था को शक की नगिह से देखेंगी।
- हालाँकि केंद्र सरकार लगातार इस कोशिश में है कि वित्तीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी के 3.3 प्रतिशत तक सीमित रखा जाए लेकिन राज्यों के इस फैसले से इस लक्ष्य की प्राप्ति में मुश्किलें आँगी।

### कैसे हल हों किसानों की समस्याएँ?

- सवाल यह है कि कर्ज़ माफ करने से किसानों की हालत सुधरनी होती तो यह काफी पहले हो चुकी होती लेकिन ऐसा नहीं हुआ लहिजा सरकारों को कर्ज़माफी की जगह किसानों की हालत सुधारने के लिये ज़रूरी उपाय करने की ज़रूरत है।
- ऐसे में ज़रूरी है कि कर्ज़माफी की जगह किसानों के उपज की खरीद, उसके रख-रखाव के साथ ही उत्पादों की मार्केटिंग पर ध्यान दिया जाए ताकि उत्पादों की कीमत में स्थिरता बनी रहे।
- किसानों की आय को बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिये ज़रूरी है कि किसानों की समस्या का स्थायी और दीर्घकालिक समाधान निकालने के उपायों पर ज़ोर दिया जाए, न कि कर्ज़माफी जैसे उपायों का सहारा लिया जाए।
- नीति आयोग ने नए भारत के लिये तैयार रणनीति में इन उपायों का ज़िक्र किया है।
- किसानों की समस्या के लॉन्ग टर्म समाधान के लिये मार्केटिंग तथा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना होगा। किसान को मार्केट से लिक करना होगा।
- सबसे अहम है कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ाना जो काफी कम है। उन राज्यों में निवेश काफी कम है जहाँ कर्ज़माफी की गई है। इन राज्यों के बजट पर दबाव है।
- उत्पादन क्षति, सूखा, अधिक वर्षा, मौसम का अनुकूल न होना, जल की कमी ऐसी समस्याएँ हैं जो किसानों का स्ट्रेस बढ़ाने के प्रमुख कारक हैं जिसका स्थायी समाधान निकालना बेहद ज़रूरी है।

### किसानों की आय दोगुनी करने की नीति आयोग की रणनीति

- केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है और इसी आधार पर कृषि नीति पर काम किया जा रहा है।
- 19 दिसंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री ने नए भारत के लिये नीति आयोग द्वारा तैयार की गई रणनीति को जारी किया, इसे 'नए भारत के लिये रणनीति @75' का नाम दिया गया है।
- इसमें किसानों की समस्याओं को दूर करते हुए उनकी आय दोगुनी करने के लिये सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी गई है।
- नीति आयोग ने कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिये नए कदमों की शुरुआत शुरू की है।
- नीति आयोग के इस रणनीतिक दस्तावेज़ में खेती की उत्पादकता और क्षमता में विकास पर ज़ोर दिया गया है।
- बाज़ारों तक अपनी पैदावार के लिये किसानों की पहुँच बढ़े उसके लिये नीति आयोग ने ई-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार का विस्तार करने को कहा है।
- कृषि उपज विपणन समिति कानून की जगह कृषि उपज पशुधन विपणन नीति लाकर कृषि क्षेत्र में किसानों को कृषि उद्यमी बनाने पर ज़ोर दिया गया है।
- नीति आयोग ने माना है कि एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार का गठन मुक्त नरियात व्यवस्था और ज़रूरी जसि कानून को समाप्त करना कृषि वृद्धि के लिये ज़रूरी है।
- कृषि क्षेत्र की दशा सुधारने के लिये ज़ीरो बजट प्राकृतिक खेती को ज़ोरदार तरीके से बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।
- नीति आयोग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को किसानों की आय बढ़ाने का एक आंशिक समाधान बताया है।
- नीति आयोग ने कृषि लागत और मूल्य आयोग की जगह एक न्यायाधिकरण गठित करने को कहा है।
- रणनीतिक दस्तावेज़ में कहा गया है कि सरकार को संवधान के अनुच्छेद 323B के प्रावधानों के अनुरूप कृषि लागत और मूल्य आयोग की जगह कृषि न्यायाधिकरण स्थापित करने पर विचार करना चाहिये।
- किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने और बाज़ार में कीमतों को गरिने से रोकने के लिये सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है।
- कृषि लागत और मूल्य आयोग की सफ़ारिशों पर 22 खरीफ और रबी फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है।

- नीतिआयोग कसिनॉ की आय बढ़ाने के लिये कृषिउपजों के आरक्षण मूल्य पर नीलामी की व्यवस्था के पक्ष में है।
- रणनीतिक दस्तावेज़ में कहा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह न्यूनतम आरक्षण मूल्य की संभावना तलाशने के लिये एक समूह बनाया जाना चाहिये जो मंडियों में उपज की नीलामी के लिये शुरुआती बट्टि हो सकता है।
- नीतिआयोग के मुताबिक, इस समूह को यह भी जाँचना चाहिये कि क्या MSP को तीन अलग-अलग मानदंडों के आधार पर तय किया जा सकता है?
- ये तीन मानदंड हैं- आवश्यकता से अधिक उत्पादित उत्पाद, घरेलू बाज़ार में कमी वाले ऐसे उत्पाद जिनकी घरेलू और वैश्विक स्तर पर उपलब्धता है और ऐसे उत्पाद जिनकी घरेलू और वैश्विक स्तर पर कमी है।
- नीतिआयोग ने भविष्य में प्रोत्साहन और कमीशन भुगतान प्रणाली के ज़रिये न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को समर्थन देने के लिये बाज़ारों में करोबार करने वाले नज़ी व्यापारियों को शामिल करने के विकल्पों की जाँच का सुझाव दिया है।
- नीतिआयोग का मानना है कि MSP या कीमतें बढ़ाना सरिफ कसिनॉ को लाभकारी रटिर्न सुनिश्चित करने की समस्या का आंशिक समाधान हो सकता है। दीर्घकालिक समाधान के लिये प्रतस्पर्धी, स्थिर और एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार का निर्माण होना चाहिये जो बेहतर मूल्य खोज को संभव बनाएगा।
- नीतिआयोग ने खेती की उत्पादकता और क्षमता के विकास के लिये सूक्ष्म सचिाई और कांटेक्ट फार्मिंग यानी अनुबंध खेती को ज़रूरी बताया है।
- कृषि नरियात के बारे में आयोग ने सुझाव दिया है कि सरकार को सुसंगत और स्थिर कृषि नरियात नीतिलानी चाहिये जो आदर्श रूप से 5 से 10 वर्ष की सोच के साथ तय हो। बीच-बीच में इस नीति की समीक्षा भी होनी चाहिये।
- आयोग ने सचिाई सुवधाओं, वपिणन सुधार, कटाई के बाद फसल प्रबंधन और बेहतर फसल बीमा उत्पादों में सुधार के माध्यम से कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने की भी बात कही है।
- कसिनॉ तक उर्वरकों की पहुँच सुनिश्चित हो इसके लिये 2022 तक यूरिया के उत्पाद में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य तय किया गया है।
- उर्वरक में सीधे नकदी लाभ देने यानी DBT लाने की पायलट परियोजना अनेक राज्यों में सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है।
- इन सबके अलावा यह ज़रूरी है कि खेती के फायदे के लिये बन रही योजनाओं और नीतियों के बारे में कसिनॉ को बेहतर जानकारी मलि सके।
- ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनकी मदद से 2022 तक कसिनॉ की आय दोगुनी करने में मदद मल्लिगी।

## भारत में कृषि

- देश के कुल कामगारों के करीब आधे रोज़गार के लिये खेती पर निर्भर हैं। हाल के सालों में देश में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं जिसके चलते कृषि पर रोज़गार के लिये निर्भरता घटी है लेकिन अभी भी खेती और कसिनान पर दबाव बना हुआ है।
- कृषि और कृषि आधारित उद्योगों का देश की अर्थव्यवस्था में 17 से 18 प्रतिशत योगदान है।
- देश के नरियात में कृषि का योगदान 16 प्रतिशत है इसके अलावा कृषि देश की तकरीबन आधी आबादी के लिये रोज़ी-रोटी का ज़रिया है।
- 2011 की जनगणना के मुताबिक, 15.97 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन खेती के लिये इस्तेमाल हो रही है। यह अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है इसके बावजूद देश में कसिनान और खेतीहर मज़दूर की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है।
- कई बार दहिाड़ी मज़दूरों की आमदनी कृषि कार्यों में लगे लोगों से भी ज़्यादा होती है। खेती में लगे ज़्यादातर कसिनान खेती से जुड़ी समस्याओं और कर्ज़ के जाल में उलझे हुए हैं।
- देश में ज़्यादातर छोटे और मझोले जोत के कसिनान हैं। देश में हर कसिनान परिवार के पास औसतन 1.08 हेक्टेयर ज़मीन है। इतनी ज़मीन से औसतन साढ़े 6 हज़ार की मासिक आय हो पाती है।
- खेती पर होने वाला मासिक खर्च कई बार इससे भी ज़्यादा होता है, जाहरि है खेती में मुनाफे की गुंजाइश काफी कम रह गई है।
- लगातार खेती पर निर्भर रहने वाले परिवारों के पास कर्ज़ के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसके चलते लोग दूसरे काम-धंधों की तरफ रुख कर रहे हैं।
- एक अनुमान के मुताबिक, देश में कृषि क्षेत्र में 10 करोड़ से ज़्यादा मज़दूर हैं, हालाँकि खेतहरि मज़दूरों की तादात लगातार कम हो रही है।
- जनगणना के मुताबिक, 1990 के दशक में 60 प्रतिशत मज़दूर खेती पर निर्भर थे। 2011 आते-आते इनकी तादात घटकर 49 प्रतिशत रह गई।
- दरअसल, ज़्यादातर मज़दूर अशिक्षित, अप्रशिक्षित और भूमहीन लोग हैं। खेती पर अतनिर्भरता ने इन लोगों को गरीबी और कर्ज़ के अँधेरे कुएँ में ढकेल दिया है।
- शहर में जनि कषेत्रों में मज़दूरों की ज़रूरत है उनमें मज़दूरी काफी कम है। इसके चलते इनके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आता और आखकारि ज़्यादातर लोग गाँव वापस लौटने को मज़बूर हो जाते हैं।
- जनवरी से दसिंबर 2003 के बीच NSS के सर्वे में पाया गया कि देश में 48.6 फीसदी कसिनान परिवार कर्ज़दार थे।
- जनवरी से दसिंबर 2013 के बीच के 70वें राउंड तक ये बढ़कर 52 फीसदी हो गए।
- 59वें दौर में कसिनान परिवारों का औसत कर्ज़ जहाँ 12,585 रुपए था वह सर्वे के 70वें राउंड में बढ़कर 47 हज़ार रुपए हो गया।
- इसकी सबसे बड़ी वज़ह खेती की कम होती जोत और खेती के इनपुट में लगातार बढ़ोतरी है।
- खेती एकमात्र उद्यम है जिसमें कसिनान को उसकी लागत के हिसाब से उपज की कीमत तय करने का अधिकार नहीं है। बजिली, पानी, खाद, बीज और मज़दूरी लगातार बढ़ रही है, खेती की लागत बढ़ रही है लेकिन उस अनुपात में कसिनान को उपज का दाम नहीं मलि रहा।
- इसके अलावा मौसम, बाज़ार की शक्तियाँ, सरकारी नीतियाँ, आयात-नरियात नीति समेत तमाम कारक हैं जो कसिनान के भाग्य का फैसला करते हैं।
- ज़्यादातर फसलों के दाम सरकार तय करती है लेकिन लागत खर्च पर न सरकार का नयित्रण है और न ही कसिनान का।

## नषिकर्ष

कसिनॉ की कर्ज़माफी पर राजनेता और अर्थशास्त्री आमने-सामने दखिाई दे रहे हैं। एक ओर राजनीतिक दल कसिनॉ की कर्ज़माफी के लुभावने वादे कर सत्ता हासलि कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर अर्थशास्त्री इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिये चुनाव आयोग से अपील कर रहे हैं। कसिनॉ की मदद के लिये बेहतर रास्ता यह हो सकता है कि उन्हें कर्ज़माफी जैसी सुवधा की बजाय खेती की ज़रूरत का सामान मुहैया कराया जाए तथा कृषि क्षेत्र में नविश बढ़ाया जाए। सरकारों को इस दशिा में पहल करने की ज़रूरत है कि कसिनॉ के लिये वे ऐसी योजनाएँ तैयार करें जिससे गरीब से लेकर संपन्न कसिनान को कर्ज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़े और वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकें।

